तत्काल

विधानसभा प्रश्न

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार

शिक्षा निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली

विधायी कार्य शाखा / प्रश्न कक्ष

संख्याः डी0ई0–25 (13) /155/ वि0कार्य / 2017–18 / विभिन्न / खण्ड–II/ 610 दिनांक 23/3/18

सेवा में,

उपसचिव, (प्रश्न कक्ष)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय,

पुराना सचिवालय, दिल्ली 110054

विषयः– विधानसभा ~~तारांकित~~ / अतारांकित / ~~अश्वासन~~ संख्या 232 दिनांक 23.3.18 के सन्दर्भ में।

महोदय,

आपकी सेवा में दिनांक 23-3-18 को विधानसभा में पूछे गये उपरोक्त ~~तारांकित~~ / अतारांकित प्रश्न / ~~आश्वासन~~ संख्या की 100 प्रतिलिपियॉ भेजने का निर्देश हुआ है। जोकि आपको प्रेषित है।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार

उप शिक्षा निदेशक,
(विधायी कार्य शाखा)

विभाग का नाम :– शिक्षा विभाग

विभाग का पता :– पुराना सचिवालय, दिल्ली–110054

अतारांकित प्रश्न संख्या :– 232

दिनांक :– 23.03.2018

प्रश्नकर्ता का नाम :– श्री ओम प्रकाश शर्मा

क्या उप मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:–

प्रश्न	उत्तर
(क) क्या यह सत्य है कि सरकार ने वर्ष 2016–17 में बच्चों पर पाठयक्रम का बोझ कम कर पुनः संगीत, नाटक, कला इत्यादि में प्रशिक्षण देने के लिए अलग से पहली बार 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था;	जी हॉ, शिक्षा निदेशालय ने वर्ष 2016–17 में 54 पायलट स्कूलों में संगीत, नाटक, कला इत्यादि में प्रशिक्षण देने के लिये रू. 5 लाख प्रति विद्यालय का प्रावधान किया था।
(ख) इस दिशा में क्या प्रगति हुई, इसकी विस्तृत जानकारी दें;	वर्ष 2016–17 में इन विद्यालयों में 65 व्यक्तिगत व 14 निजी अकादमियों के प्रशिक्षक नियुक्त किये गये थे। यह सभी स्कूलों में किया गया।
(ग) क्या स्कूलों में बच्चों पर पाठ्यक्रम का बोझ कम हुआ;	हॉ।
(घ) इसके लिए सरकार द्वारा क्या–क्या कदम उठाए गए; और	1. हिंदी, अग्रेजी, गणित, विज्ञान व सामाजिक विज्ञान विषयों में कक्षा VI से VIII तक निष्ठा व प्रतिभा ग्रुप पर केन्द्रित पाठ्यक्रम जारी किया गया। 2. कक्षा VI से VIII तक हिंदी और अंग्रेजी विषय की " Supplementary Reader " पुस्तक से केवल गतिविधियॉ कराईं गईं। इन पुस्तकों से किसी भी परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं।
(ड) वर्ष 2017–18 में इस योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई और उसमें से कितनी व्यय हुई?	वर्ष 2017–18 में इस योजना के लिये रू. 5 लाख प्रति विद्यालय आवंटित किए गए हैं। चूंकि वित्तीय वर्ष 2017–18 अभी जारी है, अतः खर्चे का ब्यौरा 31.03.2018 के बाद दिया जा सकता है। इस योजना की सफलता से प्रेरित होकर शिक्षा निदेशालय की वर्ष 2018–19 से सभी विद्यालयों में संगीत, नाटक, कला इत्यादि में प्रशिक्षण देने की योजना है। यह योजना सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। इसके तहत निजी अकादमी/व्यक्ति/गैर सरकारी संस्थानों को सरकारी विद्यालय में प्रशिक्षकों को निःशुल्क जगह उपलब्ध कराई जाऐगी। इसके एवज में प्रशिक्षकों को कम से कम 50 प्रतिशत छात्रों को निःशुल्क प्रशिक्षण देना होगा जो कि सरकारी विद्यालयों से होंगे।